सुभाषित *जो व्यक्ति किसीसे धन एवं सामग्रीकी सहायता लेनेके पश्चात अपने दिये हुए वचनका पालन नहीं करता तो वह संसारमें सबसे अधिक निकृष्ट माना जाता है।* ❑ **हितोपदेश**

चीनका फिर प्रलाप

चीन भारतसे अपने द्विपक्षीय सम्बन्धोंको सामान्य बनानेकी बातें तो करता है, जो उसकी कूटनीतिका हिस्सा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। उसकी कथनी और करनीमें जमीन-आसमानका अन्तर है। इसलिए उसकी किसी भी बातपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीनने फिर पुराना प्रलाप शुरू कर दिया है और दावा किया है कि लद्दाखकी २८ जगहें उसकी अपनी है। चीन लद्दाखको भारतकी ओरसे बनाये गये केन्द्रशासित प्रदेशको भी नहीं मानता है। भारतने इस प्रकरणमें चीनको करारा जवाब दिया है और कहा है कि लद्दाख भारतका अभिन्न अंग है और अविभाज्य हिस्सा है। भारतने कुछ दिन पूर्व ही लद्दाखमें २८ स्थानोंको आधिकारिक नाम देनेका फैसला किया था। मंगलवारको चीनकी ओरसे इसपर विरोध जताया गया था। भारतने चीनके इस अनर्गल दावेको सिरेसे खारिज कर चीनको दो-टूक जवाब दिया है। इससे सीमा मुद्देपर मतभेद फिर उजागर हुआ है, जो आपसी रिश्तोंमें कटुता उत्पन्न करने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्वे आफ इण्डियाके आधिकारिक नक्शेपर लद्दाखके २८ स्थानोंको मानक नाम दिये गये हैं। विगत दो अक्तूबर, २०२६ को भारत सरकारने लद्दाखके २८ स्थानों और भौगोलिक विशेषताओंको सर्वे आफ इण्डियाके आधिकारिक मानचित्रपर मानकीकृत नामोंके साथ दर्ज किया है। इनमें पर्वत, चोटियां, दर्रे, ग्लेशियर, घाटियां, नदियां, झील और अन्य भू-भाग शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतके आधिकारिक नक्शोंमें इन स्थानोंकी पहचानको स्पष्ट और व्यवस्थित करना तथा इनके बारेमें जागरूकता बढ़ाना है। इनमें गोगरा और हाट स्प्रिंग विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है। दोनों २०२० को भारत-चीन सैन्य गतिरोधके प्रमुख टकराव वाले क्षेत्रोंमें रहे हैं। इस मामलेमें चीनने जो बयान दिया है, वह स्थान नामकरणका विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे चीनका पुराना सीमा दावा भी स्पष्टत: दिखायी देता है। भारतने इस पूरे विवादको अपनी सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डताके स्पष्ट पुनर्पुष्टिकरणके रूपमें देखा है। लद्दाखका मौजूदा विवाद २०२० के सैन्य गतिरोधसे जुड़ा है। गलवान घाटीमें जून २०२० में हुई हिंसक झड़पमें भारतीय और चीनी सैनिकोंकी जान गयी थी। इसके बाद दोनों देशोंने पूर्वी लद्दाखमें बड़े पैमानेपर सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात किये थे। लेकिन बादमें कुछ स्थितियां बदलीं लेकिन पूरी सीमाका अन्तिम समाधान अभी नहीं हुआ है। भारत और चीनके बीचपर वास्तविक नियंत्रण रेखाके कई हिस्सोंकी संवेदनशील भौगोलिक और सामरिक स्थितिको देखते हुए भारतको इसमें किसी तरहकी ढिलाईसे बचना होगा और मजबूत दबाव बनाये रखना होगा।

लोभ-लापरवाहीका खामियाजा

बिहारके वैशाली जिलेमें मंगलवारकी रात गंगामें नाव डूबनेकी दुर्भाग्पूर्ण घटनामें १३ लोगोंकी मौत अत्यन्त दुखद है। मृतकोंमें दस लड़कियां और तीन लड़के हैं जिनकी उम्र छहसे १८ वर्ष बतायी जा रही है। छोटी नावपर क्षमतासे अधिक २० से २५ लोग सवार थे जो राधोपुरमें श्राद्ध भोजमें शामिल होने जा रहे थे। कुछ लोगोंने तैर कर अपनी जान बचायी, जबकि कई लोग लापता बताये जा रहे हैं उनकी तलाश जारी है। डूब रहे लोगोंकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तत्काल पहुंचकर १७ लोगोंको पानीसे बाहर निकाला। सभीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकोंने १३ को मृत घोषित कर दिया और तीनको गम्भीर स्थितिमें पटना मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणोंके अनुसार नावमें छेद था जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। नावमें पानी भरते ही उसमें सवार लोगोंमें अफरा-तफरी मच गयी। इस दौरान किनारे मौजूद लोग नदीमें कूद पड़े और तैरकर डूब रहे लोगोंको बाहर निकाला लेकिन तबतक बहुत देर हो चुकी थी और १३ लोगोंकी जान चली गयी। घटनापर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने मृतकोंके परिजनोंको दो-दो लाख रुपये और घायलोंको ५० हजार रुपये मददकी घोषणा की है। वहीं बिहारके मुख्य मंत्री सम्राट चौधरीने मृतकोंके परिजनोंको चार-चार लाख रुपयेकी अनुग्रह राशि देनेका ऐलान किया। इस हादसेके लिए नाविक पूरी तरह जिम्मेदार माना जायगा, जिसने छोटी नावपर क्षमतासे अधिक सवारियोंकी जगह दी जिसके चलते यह लापरवाहीका सफर साबित हुआ। ऐसा अकसर होता है कि नाविक पैसेकी लालचमें नावकी क्षमता सीमा लांघ कर सवारी बैठा लेते हैं। वे खुद तो बच निकलते हैं, क्योंकि वह अच्छे तैराक होनेके साथ अनुभवी भी होते हैं, लेकिन सवारियोंको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे नाविकोंके विरुद्ध कड़ी काररवाई होनी चाहिए जो दूसरोंके लिए सबक बने। लोगोंको भी सतर्क रहना होगा।

लोक संवाद

शक्ति उपासनासे नवीन ऊर्जाका संचार

महोदय,-भारत पर्व और त्योहारोंका देश कहा जाता है। यह पर्व हमारे जीवनमें मानों नवीनताका संचार करते हैं और हमें एक नवीन ऊर्जासे भर देते हैं। इन्हीं पर्वोंमें नवरात्र अपने आपमें महान पर्व है, जिसमें शक्ति स्वरूपा मां दुर्गाकी उपासना भी हमारे अन्दर सात्विकताका संचार करती है। वही आदि शक्ति ही सब प्राणियोंमें शक्ति, निद्रा, विद्या, तुष्टि आदि रूपोंमें विद्यमान है। उन्हींसे यह सारा जगत व्याप्त है। उपासनाका अर्थ है समीप और आसनका अर्थ बैठना है। अर्थात् हम जिनकी उपासना कर रहे हैं उनका चिंतन-मनन करें। नवरात्र पर्वपर देवीकी विभिन्न रूपोंमें उपासना भी हमारे भीतर एक नवीन ऊर्जाका संचार कर देती है। दो गुप्त नवरात्र और वासंतिक और शारदीय नवरात्र होते हैं। शारदीय और वासंतिक नवरात्र ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गुप्त नवरात्रमें भी शक्ति स्वरूपा मां जगदंबाकी उपासना, पूजन, अर्चना हमें मनोवांछित फल प्रदान करती है और शक्तिके बिना न तो हमारा अस्तित्व है और न ही इस संसारका। यह पर्व मानों हमें यही स्मरण दिलाता है कि कोई अदृश्य शक्ति हैं जिनसे यह सारा संसार व्याप्त और गतिमान है। मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत दुर्गा सप्तशतीमें भगवती दुर्गा और उनकी महिमाका विस्तारसे वर्णन है कि वही शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा दानव शक्तियोंका नाश करती हैं और उन्होंने देवताओंसे स्वयं कहा है कि जब जब दानवीय शक्तियोंका उत्थान होगा अर्थात् अधर्म बढ़ेगा तब अलग-अलग स्वरूपोंमें वही शक्ति स्वरूपा दुर्गा अवतार लेकर असुरोंका विनाश करेंगी। भगवान शिव और पार्वती भी शिव और शक्ति माने जाते हैं। भगवान रामने भी रावणपर विजय प्राप्त करनेके लिए इन्हीं शक्तिकी उपासना की थी। इस पर्वपर घर-घरमें मां दुर्गाका पूजन अर्चन, मांके सुमधुर गीत, कन्या पूजन, हवनसे मानों वातावरणमें भी एक नवीन चेतनाका संचार होता है। नारी सम्मान हमारे देशकी संस्कृति रही है। यह पर्व भी हमें यही सीखाता है कि स्त्री हर रूपमें आदरणीय है। यह पर्व देवीकी उपासना पूजन और उनका सतत स्मरणसे हमें अपने भीतर एक नवीन ऊर्जाका संचार करनेका अवसर है। शारदीय नवरात्रिसे ऋतुमें परिवर्तन होने लगता है और प्रकृति सर्दीकी चादरमें सिकुड़ने लगती है, ऐसेमें नवरात्रिकी नौ दिनोंकी अवधिमें उपासक संतुलित और सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना ध्यान चिंतन और मननमें लगाकर स्वयंको भीतरसे शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे ऋतु परिवर्तनका उनकी सेहतपर बुरा असर नहीं पड़ता। नवरात्रिके नौ व्रत रखनेसे न केवल स्वयंको मानसिक रूपसे भीतरसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है, बल्कि उत्तम स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी इसके कई लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रिका व्रत रखते हैं, वे दूसरोंकी तुलनामें आरोग्य जीवन जीते हैं। दरअसल नवरात्रि व्रतके दौरान लोग गरिष्ठ भोजनसे दूर रहते हैं और फल ग्रहण करते हैं, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है, तनावकी समस्या दूर होती है और त्वचामें निखार भी बढ़ता है। नवरात्रि व्रत रखनेसे शरीरमें कोलेस्ट्रॉलका स्तर भी कम हो जाता है। नौ दिनोंतक पूरे संयमके साथ व्रत रखनेसे आध्यात्मिक फायदोंके अलावा पेटको आराम मिलनेसे उसकी सेहत अच्छी होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, गठिया, अस्थमा, एलर्जी, हृदय रोगोंमें आराम मिलता है, नींद बेहतर होती है, उम्र लंबी होती है तथा कैंसर, अल्जाइमर जैसी गम्भीर बीमारियोंका जोखिम भी कम होता है। -**अखिलेश कुमार मिश्र, वाराणसी।**

विरोधके अधिकारपर सर्वोच्च टिप्पणी

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने, सरकार बनाने और शासन चलानेकी व्यवस्थाका नाम नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति नागरिकोंको अपनी बात कहने, असहमति व्यक्त करने और सरकारकी नीतियोंपर प्रश्न उठानेकी स्वतंत्रता देनेमें निहित है। दिल्लीमें निर्वाचन प्रक्रियाको लेकर हुए विरोध प्रदर्शनोंके बीच सुप्रीम कोर्टका हस्तक्षेप अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

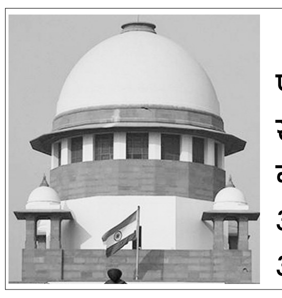
❑ **महेन्द्र तिवारी**

न्याय जिस लोकतांत्रिक व्यवस्थामें नागरिक अपनी शिकायतें खुलकर सामने रख सकें, शांतिपूर्ण ढंगसे विरोध कर सकें और अपनी मांगोंके समर्थनमें आवाज उठा सकें, वही व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्योंको मजबूत करती है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्थाके बीच टकरावकी स्थिति पैदा होती है, तब नागरिक अधिकारोंकी रक्षा और कानूनका पालन सुनिश्चित करना प्रशासनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। दिल्लीमें निर्वाचन प्रक्रियाको लेकर हुए विरोध प्रदर्शनोंके बीच सर्वोच्च न्यायालयका हस्तक्षेप इसी संदर्भमें महत्वपूर्ण है। १० अक्तूबर २०२६ को दिल्लीमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारके इस्तीफे और मतदाता सूचीके विशेष गहन पुनरीक्षणको लेकर विरोध प्रदर्शनका आह्वान किया गया था। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलोंने निर्वाचन प्रक्रियामें कथित अनियमितताओंको लेकर सवाल उठाये। उनका आरोप था कि मतदाता सूचीमें बदलावकी प्रक्रियासे कुछ वर्गोंके मतदाताओंके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोगने प्रक्रियामें पक्षपातके आरोपोंको खारिज किया है। सत्तारूढ़ दलने भी विपक्षके आरोपोंपर आपत्ति जतायी है। इसलिए इस पूरे विवादमें आरोपों, आधिकारिक स्पष्टीकरणों और प्रमाणित तथ्योंको अलग-अलग समझना आवश्यक है। प्रदर्शनके मद्देनजर दिल्लीके कई हिस्सोंमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गयी। मेट्रो स्टेशनोंको बंद करने, आवागमन सीमित करने और इंटरनेट सेवाओंपर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमोंकी खबरें सामने आयीं। बड़ी संख्यामें लोगोंको हिरासतमें लिये जानेकी सूचना भी मिली। इन कदमोंसे केवल प्रदर्शनकारियोंकी गतिविधियां प्रभावित नहीं हुईं, बल्कि आम नागरिकोंकी आवाजाही, दैनिक कामकाज और सार्वजनिक परिवहनपर भी असर पड़ा। ऐसेमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखनेके लिए किये गये प्रबंध किस सीमातक आवश्यक और उचित थे।

इसी पृष्ठभूमिमें ११ अक्तूबर २०२६ को सर्वोच्च न्यायालयने विशेष सुनवाई करते हुए अधिकारियोंको कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिये। न्यायालयने कहा कि शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगोंको कानूनमें निर्धारित प्रक्रियाके बिना हिरासतमें नहीं लिया जाना चाहिए। उसने मेट्रो और रेल सेवाओंको सामान्य रूपसे चलाने, शहरमें यातायात नियमोंके अधीन लोगोंकी आवाजाही सुनिश्चित करने तथा इंटरनेट सेवाओंको अनावश्यक रूपसे बाधित न करनेपर जोर दिया। न्यायालयने सड़कोंपर लगाये गये अवरोधोंकी तत्काल समीक्षा करने और अदालतोंतक लोगोंकी पहुंच सुनिश्चित करनेके निर्देश भी दिये। इन निर्देशोंके साथ यह स्पष्ट रखा गया कि सार्वजनिक व्यवस्थाकी वास्तविक आवश्यकता होनेपर कानूनके अनुसार उचित प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

इस घटनाक्रमका महत्व इसलिए भी है कि संविधान नागरिकोंको केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि शासनकी शक्तियोंकी सीमाएं भी निर्धारित करता है। भारतीय संविधानका अनुच्छेद-१९ नागरिकोंको अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारोंके एकत्र होनेका अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार लोकतंत्रमें नागरिक सहभागिताका आधार हैं। हालांकि इनपर संविधानमें निर्धारित आधारोंपर उचित प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। इसलिए विरोध करनेकी स्वतंत्रताका अर्थ कानूनसे ऊपर होना नहीं है और न ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखनेका अर्थ नागरिकोंके अधिकारोंको मनमाने ढंगसे सीमित करना है।

प्रशासनकी जिम्मेदारी है कि वह संभावित हिंसा, यातायात अवरोध और सार्वजनिक संपत्तिको होने वाले नुकसानसे बचानेके लिए आवश्यक कदम उठाये। लेकिन किसी संभावित खतरेकी आशंकाके आधारपर सभी लोगोंकी आवाजाही रोक देना या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियोंको बिना वैधानिक आधारके हिरासतमें लेना उचित नहीं माना जा सकता। प्रतिबंधोंका औचित्य, उनकी अवधि और उनका दायरा परिस्थितियोंके अनुरूप होना चाहिए। जहां सीमित व्यवस्थासे समस्याका समाधान संभव हो, वहां व्यापक प्रतिबंधोंके कारण आम नागरिकोंको अनावश्यक परेशानीमें डालनेसे बचना चाहिए।



सर्वोच्च न्यायालयके हस्तक्षेपसे संदेश सामने आया है कि सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताको परस्पर विरोधी मानकर नहीं चलना चाहिए। कानूनका उद्देश्य अधिकारोंको समाप्त करना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करते हुए समाजमें व्यवस्था बनाये रखना है। लोकतंत्रकी वास्तविक मजबूती तब दिखती है, जब नागरिक बिना भयके अपनी बात रख सकें, प्रशासन निष्पक्षतासे अपने दायित्व निभाये और न्यायपालिका आवश्यकता पड़नेपर संवैधानिक सीमाओंकी रक्षा करे। विरोधकी आवाज सुनना, असहमतिका सम्मान और कानूनका समान रूपसे पालन सुनिश्चित करना भी उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्थाकी पहचान है।

दिल्ली जैसे महानगरमें मेट्रो और रेल सेवाएं केवल यातायातके साधन नहीं हैं। लाखों लोग प्रतिदिन इन सेवाओंके माध्यमसे अपने कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक स्थानोंतक पहुंचते हैं। अचानक परिवहन सेवाएं बंद होनेसे विद्यार्थियोंकी पढ़ाई, कर्मचारियोंकी उपस्थिति, मरीजोंकी चिकित्सा और छोटे कारोबारियोंकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार इंटरनेट सेवाएं आज शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, संचार और आपातकालीन सहायताका महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इनके व्यापक प्रतिबंधका प्रभाव प्रदर्शन स्थलसे कहीं अधिक दूरतक पहुंचता है।

इस संदर्भमें सर्वोच्च न्यायालयकी भूमिका केवल किसी एक प्रदर्शनको लेकर आदेश देनेतक सीमित नहीं है। न्यायपालिकाका दायित्व यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रशासनिक काररवाई संविधान और कानूनके अनुरूप हो। जब नागरिकोंको लगता है कि उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब न्यायालयसे राहतकी अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्थाका स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि न्यायिक हस्तक्षेपका अर्थ यह नहीं है कि किसी विवादमें एक पक्षके सभी आरोप स्वत: सिद्ध हो गये। न्यायालयके अंतरिम निर्देश, प्रारंभिक टिप्पणियां और अंतिम निर्णय अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। दिल्लीके मामलेमें भी अधिकारियोंसे जवाब और अनुपालन संबंधी जानकारी मांगी गयी है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों और आगेकी न्यायिक प्रक्रियाके आधारपर ही निकाला जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रियासे संबंधित विवादका एक व्यापक पक्ष जनताका विश्वास है। चुनाव लोकतंत्रकी बुनियादी प्रक्रिया हैं और मतदाता सूची उनकी विश्वसनीयताका महत्वपूर्ण आधार है। मतदाता सूचीका पुनरीक्षण आवश्यक हो सकता है, क्योंकि समयके साथ मृत्यु, स्थान परिवर्तन और अन्य कारणोंसे अभिलेखोंमें बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रियामें किसी पात्र नागरिकका नाम गलत तरीकेसे हटना उसके मताधिकारको प्रभावित कर सकता है। इसलिए सूचीमें संशोधन करते समय पारदर्शिता, स्पष्ट मानदंड, उचित सूचना और शिकायतोंके निवारणकी प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक दलों और नागरिकोंकी आपत्तियोंका समाधान प्रमाणोंके आधारपर होना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन भी लोकतंत्रमें संवादका माध्यम हैं। नागरिक जब किसी निर्णयसे असहमत होते हैं तो शांतिपूर्ण ढंगसे अपनी मांग रखना उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही प्रदर्शन आयोजित करने वालोंका दायित्व है कि वे कानूनका पालन करें, हिंसासे बचें और दूसरे नागरिकोंके अधिकारोंका सम्मान करें। प्रशासनको भी प्रदर्शनकारियोंके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि तनाव कम किया जा सके और सार्वजनिक सुविधाएं बाधित न हों। दोनों पक्षोंकी जिम्मेदारी और संयमसे ही ऐसी परिस्थितियोंका समाधान संभव है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि लोकतांत्रिक असहमतिको केवल कानून-व्यवस्थाकी समस्याके रूपमें न देखा जाय। असहमति किसी भी जीवंत लोकतंत्रका स्वाभाविक अंग है। उसी प्रकार हर विरोधको स्वत: उचित मान लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसकी प्रकृति, उद्देश्य और तरीकेका मूल्यांकन कानून तथा तथ्योंके आधारपर किया जाना चाहिए। सरकार, प्रशासन, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और नागरिक समाज सभीकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालयके हस्तक्षेपसे एक बार फिर यह संदेश सामने आया है कि सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताको परस्पर विरोधी मानकर नहीं चलना चाहिए। कानूनका उद्देश्य अधिकारोंको समाप्त करना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करते हुए समाजमें व्यवस्था बनाये रखना है। लोकतंत्रकी वास्तविक मजबूती तब दिखाई देती है, जब नागरिक बिना भयके अपनी बात रख सकें, प्रशासन निष्पक्षतासे अपने दायित्व निभाये और न्यायपालिका आवश्यकता पड़नेपर संवैधानिक सीमाओंकी रक्षा करे। विरोधकी आवाज सुनना,

विकासमें युवा शक्तिका योगदान

विद्यार्थी राष्ट्रकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनकी आंखोंमें पलने वाले सपने, मनमें उठने वाले विचार और कर्ममें दिखने वाला संकल्प ही देशके भविष्यकी दिशा निर्धारित करता है।

❑ **प्रो.मनोज डोगरा**

आजके विद्यार्थी ही कलके वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासक, उद्यमी, सैनिक और राष्ट्रनिर्माता हैं। इसलिए विद्यार्थियोंकी प्रतिभाको निखारना, उन्हें सही दिशा देना और उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना केवल परिवार या शिक्षण संस्थानोंकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाजका दायित्व है। इसी संदर्भमें विश्व विद्यार्थी दिवसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतमें १५ अक्तूबरको पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओंके प्रेरणास्रोत डा. एपीजे अब्दुल कलामकी जयंतीके अवसरपर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिवसका उद्देश्य विद्यार्थियोंके जीवनमें शिक्षा, ज्ञान, अनुशासन, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोणके महत्वको रेखांकित करना है। डा. कलामका संपूर्ण जीवन इस बातका प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियोंमें जन्म लेने वाला व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके पास बड़े सपने देखनेका साहस और उन्हें साकार करनेके लिए निरन्तर परिश्रम करनेका संकल्प हो।

डा. कलामका जीवन विद्यार्थियोंके लिए प्रेरणा- डा. कलामका जीवन संघर्ष, सादगी, अनुशासन और समर्पणकी अनुपम मिसाल है। तमिलनाडुके रामेश्वरममें एक साधारण परिवारमें जन्मे कलामने कठिन परिस्थितियोंके बावजूद शिक्षाके प्रति अपनी लगनको कभी कम नहीं होने दिया। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियोंके माध्यमसे उन्होंने भारतके अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमोंमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष २००२ में वह भारतके राष्ट्रपति बने, लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पदपर पहुंचनेके बाद भी उनका सबसे प्रिय परिचय एक शिक्षकका ही रहा। डा. कलामका विश्वास था कि बच्चों और युवाओंके भीतर देशको बदलनेकी क्षमता है। वह विद्यार्थियोंसे संवाद करते, उनके प्रश्नोंको प्रोत्साहित करते और उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करनेकी प्रेरणा देते थे। उनका जीवन संदेश देता है कि सफलता केवल संसाधनोंकी प्रचुरतासे नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरन्तर अभ्यास और सकारात्मक सोचसे प्राप्त होती है। आज जब विद्यार्थी परीक्षा, प्रतिस्पर्धा और भविष्यकी अनिश्चितताओंके दबावसे गुजर रहे हैं, तब कलामके विचार पहलेसे कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। विद्यार्थियोंको यह समझना होगा कि असफलता जीवनका अंत नहीं, बल्कि अपनी कमियोंको पहचानकर आगे बढ़नेका अवसर है। शिक्षाका उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, वर्तमान समयमें शिक्षाको अक्सर परीक्षामें प्राप्त अंकों, डिग्रियों और नौकरी हासिल करनेके साधनके रूपमें देखा जाता है। निस्संदेह रोजगार प्राप्त करना शिक्षाका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन शिक्षाका वास्तविक लक्ष्य इससे कहीं व्यापक है। शिक्षा व्यक्तिको विवेकशील बनाती है, सही और गलतके बीच अंतर करना सिखाती है तथा समाजके प्रति उसकी जिम्मेदारियोंका बोध कराती है। यदि कोई विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त कर ले, लेकिन उसमें ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारीका अभाव हो तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जायगी। शिक्षण संस्थानोंका उद्देश्य केवल सफल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकोंका निर्माण करना भी होना चाहिए। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा व्यवस्थाकी है, जिसमें किताबी ज्ञानके साथ व्यावहारिक अनुभव, नैतिक मूल्य, संवाद कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधानकी क्षमताको भी समान महत्व मिले। विद्यार्थियोंको प्रश्न पूछने, नये विचार प्रस्तुत करने और अपनी गलतियोंसे सीखनेके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न करने वाला विद्यार्थी ही आगे चलकर अनुसंधानकर्ता और नवाचारक बन सकता है।

डिजिटल युगमें विद्यार्थी और नयी चुनौतियां- इक्कीसवीं सदीका विद्यार्थी ऐसे दौरमें शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जहां मोबाइल फोन, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल माध्यमोंने ज्ञानतक पहुंचको आसान बना दिया है। आज घर बैठे दुनियाके प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानोंकी अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। आनलाइन कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयोंने सीखनेके नये अवसर उपलब्ध कराये हैं। लेकिन इन सुविधाओंके साथ कुछ गम्भीर चुनौतियां भी सामने आयी हैं। सोशल मीडियाका अत्यधिक उपयोग, मोबाइलपर अनावश्यक समय बिताना, गलत सूचनाओंका प्रसार और डिजिटल मनोरंजनकी लत विद्यार्थियोंकी एकाग्रताको प्रभावित कर सकती है। कई विद्यार्थी दूसरोंकी उपलब्धियोंसे अपनी तुलना करके तनावका अनुभव करते हैं और अपने आत्मविश्वासको कमजोर कर लेते हैं। तकनीक अपने आपमें न अच्छी है और न बुरी, उसका उपयोग किस उद्देश्यसे किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियोंको डिजिटल साधनोंका इस्तेमाल ज्ञान अर्जित करने, नयी क्षमताएं विकसित करने और रचनात्मक कार्योंके लिए करना चाहिए। उन्हें यह भी सीखना होगा कि इंटरनेटपर उपलब्ध प्रत्येक जानकारी सत्य नहीं होती। तथ्योंकी जांच करना, विश्वसनीय स्रोतोंको पहचानना और अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करना आजकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षाका दबाव- विद्यार्थियोंके सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियोंमेंसे एक मानसिक दबाव भी है। अच्छे अंक प्राप्त करने, प्रतियोगी परीक्षाओंमें सफल होने और मनचाहा करियर चुननेकी दौड़में कई विद्यार्थी तनावका सामना करते हैं। कुछ मामलोंमें अभिभावकोंकी अत्यधिक अपेक्षाएं और समाजमें सफलताकी सीमित परिभाषा इस दबावको और बढ़ा देती है। यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थीकी रुचि, क्षमता और सीखनेकी गति अलग होती है। सभी विद्यार्थियोंसे एक जैसी उपलब्धियोंकी अपेक्षा करना उचित नहीं है। किसीकी रुचि विज्ञानमें हो सकती है तो कोई साहित्य, संगीत, खेल, कला या उद्यमितामें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अभिभावकों और शिक्षकोंको विद्यार्थियोंकी तुलना दूसरोंसे करनेके बजाय उनकी व्यक्तिगत प्रगतिपर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल विकसित भारतका सपना युवा पीढ़ी ही साकार करेगी।



ध्यानकी प्रक्रिया

❑ **ओशो**

ध्यानका अर्थ है, एक ऐसी अवस्था, जब जाननेको कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ जानने वाला ही बचा। उससे छुटकारेका कोई उपाय नहीं है। लाख भागो पहाड़ोंपर और रेगिस्तानोंमें, चांद-तारोंपर, लेकिन तुम्हारा जानने वाला तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि वह तुम हो, वह तुम्हारा अस्तित्व है। रोज घड़ीभर, कभी भी सुबह या सांझ या दोपहर, इस अनूठे आयामको देना शुरू कर दो। बस आंख बंदकर बैठ जाओ। जब मैं कहता हूं कि घड़ी आधा घड़ीको आंख बंद करके बैठ जाओ तो तुमसे मैं यह कहा रहा हूं कि घड़ी आधा घड़ीको दूसरोंको भूल जाओ। चौबीस घंटे पड़े हैं। तेईस घंटे सारे संसारको दे दो, बाजारको दे दो, दुकानको दे दो, मकानको दे दो, जिसको देना हो, उसको दे दो। लेकिन क्या तुम इतने भी अधिकारी नहीं हो कि एक घंटा अपने लिए बचा लो। शायद चौबीस घंटा बचाना बहुत मुश्किल है एक घंटा बचाना आसान हो सकता है। फिर मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि इस घंटेको बचानेके लिए तुम हिमालयकी किसी गुफामें बैठो। तुम्हारा घर पर्याप्त है और सबसे ज्यादा आसान जगह है। क्योंकि वहां जो भी है, उससे तुम्हें परिचय है और एक घंटेके लिए उस सबको भूल जाना कठिन नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी ही वह घड़ी आ जाती है कि तुम चुपचाप बैठे ही रहते हो। मूर्तियां आयंगी, मत रस लेना उनमें, न पक्षमें और न विपक्षमें। आने देना और जाने देना। रास्ता है, मनकी राह है, चलती है। तुम राहके किनारे बैठे देखते रहना और तुम चकित होओगे, इस जीवनके सबसे बड़े रहस्यसे चकित होओगे कि यदि तुम साक्षी भावसे, जैसे तुम्हें कुछ लेना-देना नहीं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तुम गुमसुम चुपचाप सड़कके किनारे बैठे ही रहना। जल्दी ही वह घड़ी आ जायगी कि यह रास्तेकी भीड़ कम होने लगेगी, क्योंकि इस भीड़के रास्तेपर होनेका कारण है, तुमने इसे निमंत्रण दिया है। तुमने अबतक इसका स्वागत किया है। यह बिना बुलाई नहीं है और जब यह देखेगी कि तुम इतनी उपेक्षासे भर गये हो कि तुम लौटकर भी नहीं देखते, कौन आया, कौन गया, अच्छा था या बुरा, सुंदर था या कि असुंदर, अपना था कि पराया, यह भीड़ धीरे-धीरे विदा होने लगेगी। ध्यानकी प्रक्रिया बड़ी सरल है।

नये युगमें पुलिसकी विशेष भूमिका

❑ **अजय सिंघल**

नब्बेके दशकमें, एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारीके तौरपर जब मैं पहली बार किसी थानेमें गया तो मुझे आज भी अच्छेसे याद है कि वहां मुंशी हैड कांस्टेबलके हाथसे लिखा रोजनामचा (रजिस्टर), टेबलपर रखा काले रंगका भारी-भरकम डायल वाला लैंडलाइन फोन, जिसकी रिंगटोन अपनी मर्जीसे सुनाई देती और फील्डमें जानेको तैयार कुछ बीट कांस्टेबल। तब पुलिस दक्षता इस बातसे आंकी जाती थी कि पुलिस कितनी जल्दी मौकेपर पहुंची और कितने लोगोंको गिरफ्तार किया।पर बीते तीन दशकोंमें अंग्रेजोंके जमानेकी पुलिसके मॉडलका नजरिया पूरी तरहसे बदल गया। सरकारने अंग्रेजोंकी गुलामीके जमानेके सीआरपीसी १८६१ जैसी अपराधकी धाराओंको बदल १ जुलाई, २०२४ से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) जैसे तीन नये आपराधिक कानून लाकर देशकी कानून व्यवस्थामें एक क्रांतिकारी बदलाव किया।

साथ ही टैक्नोलॉजी आधारित नये दौरकी पुलिसने जन-सुरक्षाको और अधिक मजबूत करनेकी दिशामें खुफिया जानकारी, डाटा और सामुदायिक जरूरतोंका लक्ष्य नये सिरेसे तय किया कि अपराधियोंपर काररवाईके अलावा पुलिसको अपराध घटित होनेसे पहले ही कैसे रोकने हैं। परम्परागत पुलिसिंग अब टैक्नोलॉजी आधारित अपराध निवारककी भूमिकाकी ओर तेजीसे बढ़ रही है। हरियाणामें ११२ डायल करके कोई भी व्यक्ति इस एक नंबरसे ही पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य सेवाओंतक पहुंच सकता है। इस नंबरपर हर साल ५० लाखसे ज्यादा आने वाली कॉल्ससे पुलिसकी शहरों और गांवोंमें पहुंच औसत सात मिनटमें संभव हुई है। रातके अंधेरेमें जब कोई अकेली महिला खतरेके सायेमें अपने मोबाइल फोनपर दुर्गा शक्ति ऐप बटन दबाती है तो उसकी मौजूदा लोकेशन पुलिसके कमांड सैंटरको जाती है। यह घरसे दूर एक कामकाजी महिलाकी सुरक्षाके लिए टैक्नोलॉजी आधारित एक अनूठी पहल है।

हैल्पलाइन १९३० पुलिस अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियोंके साथ जुड़ी है, जहां साइबर अपराध संबंधी हर दिन करीब ५००० काल आती हैं और बैंक खातेसे पैसा निकलनेसे पहले संदिग्ध ट्रांसफर फ्रीज कर दिया जाता है। साइबर फ्रॉडके मामले रोकनेमें देशमें अव्वल हरियाणामें करीब ४० फीसदी पैसा साइबर फ्रॉड पीड़ितोंको वापस दिलाया गया है। एक लाख रुपयेसे अधिकके साइबर फ्रॉड वाली किसी भी आनलाइन शिकायतपर अपने आप जीरो एफआईआर थानेके क्षेत्राधिकारकी बाधाके बिना देशके किसी भी इलाकेमें दर्ज हो रही है। हरियाणा पुलिसका 'अभेद्य' ऐप अब अज्ञात अंतरराष्ट्रीय जबरन वसूली फोन कॉलको संबंधित लोगोंतक पहुंचनेसे पहले ही रोकता है। दोहरा ओटीपी नंबर, संदिग्ध यूपीआई लेन-देनको ब्लॉक करता है, जिससे 'डिजिटल अरैस्ट' जैसे घोटालेपर अंकुश लगाया जा रहा है। ईगल ऐपसे ड्यूटीपर तैनात पुलिस अधिकारी हिरासतमें लिये किसी व्यक्तिके चेहरेकी तुरन्त तुलना अपराधियोंके डाटाबेससे कर फर्जी लोगोंको पकड़ सकता है।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) अपराध स्थलसे मिले धुंधले फिंगरप्रिंटको कुछ ही सैकेंडमें राष्ट्रीय रिकॉर्डमें मौजूद एंट्रीसे मिलान करते हैं। स्मार्ट ई-बीट जीपीएससे पुलिस फोर्सकी गश्त दर्ज होती है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नैटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) पुलिस थानोंको अदालतों, जेलों और फॉरैंसिक सुविधाओंसे जोड़ता है। ई-साक्ष्य सुनिश्चित करता है कि अपराध स्थलका सुबूत बिना बदले असल हालतमें अदालततक सुरक्षित पहुंचे। यहांतक कि गुमनाम लोगोंको भी अब नाम मिल रहा है। एआई सहायक व्यवस्था अज्ञात शवोंके चेहरे और फिंगरप्रिंटको लापता व्यक्तियोंके डाटाबेससे मिलाती है, जिससे सालोंसे गुम अपनोंका इंतजार कर रहे परिवारोंको सुकून मिलता है। पुलिसके डिजिटल डैशबोर्ड दिखाते हैं कि कहां शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं, ताकि संबंधित पुलिस कर्मीकी जवाबदेही तय हो।

दुर्घटनाका डाटा 'हीट मैप' में बदल गया है, जो इंजीनियरोंको दिखाता है कि कहां किसी सड़कके तीखे मोड़को नये सिरेसे डिजाइन करना है, ताकि दुर्घटनाके समय 'गोल्डन ऑवर' घटानेमें मदद मिले। मोटरवेपर नंबर-प्लेट पहचान कैमरे लगातार स्थितिपर नजर रखते हैं और भागने वाले वाहनोंका ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी बनाते हैं। 'हरसमय' नामका पोर्टल नागरिकोंको एफआईआरकी कॉपी या सत्यापन प्रमाणपत्रके लिए लम्बी लाइन लगानेमें लगनेसे बचाता है, थानेके काउंटरपर क्यूआर कोड फीडबैक हर नागरिकको अपनी राय सांझी करनेका मौका देता है। पुलिसकी कार्यशैलीमें बड़ा सुधार सर्वर रूम या किसी सॉफ्टवेयरसे कहीं आगे पुलिसके मानवीय व्यवहारपर टिका है। तेजीसे बदलती दुनियामें नये दौरकी पुलिसका प्रदर्शन केवल इस बातसे नहीं आंका जा सकता कि पुलिसने टैक्नोलॉजी आधारित कितने ऐप लांच किये, बल्कि पुलिसकी दक्षता इस बातसे आंकी जा रही है कि कितने अपराध होनेसे पहले ही रोक दिये गये।

(लेखक हरियाणामें पुलिस महानिदेशक हैं।)